विकासशील देशों पर न थोपे शर्तें

कार्बन उत्सर्जन पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने अमीर देशों को घेरा

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर यूरोप के विकसित देशों को खूब खरी खोटी सुनाई. जर्मनी की राजधानी बर्लिन में उन्होंने कहा कि दुनिया जिस पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है, उसके लिए भारत जैसे विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है.

उन्होंने सवाल उठाया कि वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किसने किया और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में किन देशों की भूमिका रही है. उन्होंने बिना हिचके अमीर देशों को जिम्मेदार ठहराया. गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की लगभग 17 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसका योगदान तीन प्रतिशत से भी कम है. इसके उलट, यूरोप की आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग तीन से चार प्रतिशत होने के बावजूद उसके ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन में योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यूरोप के लोगों का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन आज भी भारत की तुलना में काफी अधिक है. ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों की जिम्मेदारियां तय करते समय उनके ऐतिहासिक योगदान और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है.

> भारत को अभी अपनी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करनी हैं और करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है. ऐसे में भारत से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह विकास की अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके उन्हीं शर्तों पर काम करे, जो पहले से विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होती हैं. उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक है, लेकिन उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है.

एलजी, सोनी, हेवल्स और विजय सेल्स दे रहे कई त्योहारी ऑफर

नई दिल्ली. त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही देश भर के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है. बिक्री को बढ़ावा देने बाजार में उतरी प्रमुख कंपनियों ने कई तरह की आकर्षक योजनाएं शुरू की हैं. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अपनी 'सेलिब्रेशन ऑफ ट्रस्ट' सेल के तहत उत्पादों पर 55 फीसदी तक की भारी छूट और 26 फीसदी तक का बैंक कैशबैक देने की घोषणा की है. इसके अलावा, साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर की खरीद पर मिनी रेफ्रिजरेटर मुफ्त मिल रहा है. वहीं, हेवल्स के कंज्यूमर ब्रांड 'लॉयड' ने 'फेस्टिव ऑफ फॉर्च्यून' कैंपेन के तहत 100 करोड़ रुपये तक के लाभ, आकर्षक गिफ्ट कूपन एसयूवी कार जीतने का मौका पेश किया है.

डेटा लीक से डिजिटल फ्रॉड का खतरा

- एसबीआई ने खाताधारकों को सुरक्षा सलाह जारी की
- डार्क वेब पर पहुंचे एसबीआई ग्राहकों के रिकॉर्ड

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर. भारतीय स्टेट बैंक ने हाल में हुई एक साइबर घटना को लेकर ग्राहकों के लिए जानकारी साझा की है. इस घटना में कुछ ग्राहकों का डाटा शामिल होने की पहचान हुई है. ऐसे ग्राहकों को बैंक ने ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिये अलग-अलग सूचना दी है. हालांकि, बैंक ने अपने संदेश में यह साफ किया है कि ग्राहकों के खातों में जमा रकम सुरक्षित है.

एसबीआई ने अपने बयान में कहा है कि ग्राहकों के खाते में जमा रकम और उनके पैसे बैंक के पास सुरक्षित हैं. बैंक के इस बयान से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि साइबर घटना में किसी तरह का नुकसान हुआ ही नहीं. बैंक ने डाटा से जुड़ी घटना की जानकारी दी है, लेकिन साझा किए गए संदेश में यह नहीं बताया है कि कितने ग्राहकों का डाटा प्रभावित हुआ, कौन-सी जानकारी सामने आई या साइबर घटना कैसे हुई.

एसबीआई के ग्राहकों के डाटा से जुड़ा मामला 21 अक्तूबर को सामने आया, जब बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि डार्क वेब पर उपलब्ध करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में 3,897 रिकॉर्ड ऐसे मिले, जिनमें ग्राहकों की निजी जानकारी शामिल थी.

> बैंक को 16 अक्तूबर को अपने थ्रेट इंटेलिजेंस सेवा प्रदाता, डिफेंस साइबर एजेंसी और भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल से डाटा उजागर होने की आशंका को लेकर अलर्ट मिले थे. बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय सावधान रहने की सलाह दी है. एसबीआई ने साफ कहा है कि अपना ओटीपी, एटीएम या बैंकिंग पिन और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें. अगर किसी अनजान नंबर से संदिग्ध कॉल आए या कोई शक वाला मैसेज अथवा ईमेल मिले, तो सतर्क रहें. ऐसी जानकारी साझा करने से बचें, जिसका इस्तेमाल कोई आपके बैंक खाते तक पहुंचने के लिए कर सकता है.

2 लाख के नीचे फिसली चांदी सोना 1,42,750 रुपये

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर. धनतेरस, दिवाली और शादी-ब्याह के सीजन में सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. सोने और चंदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है.

घरेलू बाजार में 23 अक्टूबर 2026 को सोने और चांदी दोनों के भाव नीचे आ गए. 24 कैरेट सोना 0.61% गिरकर 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी की कीमत 1.93% टूटकर 1,96,510 रुपये प्रति किलो पर आ गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने पर दबाव बना हुआ है. ऐसे में नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले फैसले पर है, जिसका असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुरुवार देर रात सोना दो सप्ताह से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गया. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है. इससे निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़ी अगली घोषणा पर टिक गई है. स्पॉट गोल्ड 2.2% गिरकर 4,051.55 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 2% की गिरावट दर्ज हुई.

बेंगलुरु में टस्क का बयान : वैश्विक बाजारों पर कब्जा करेंगे दोनों देश

बेंगलुरु, 23 अक्टूबर. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने शुक्रवार को 'भारत-पोलैंड व्यापार मंच' को संबोधित करते हुए दोनों देशों से प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा और वैमानिकी के क्षेत्रों में अपने सहयोग को गहरा करने की अपील की. टस्क ने जोर देकर कहा कि अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वारसॉ यात्रा के दौरान तय की गई रणनीतिक साझेदारी को अब वास्तविक संयुक्त उद्यमों में बदलने की सख्त जरूरत है. वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में बेंगलुरु की सराहना करते हुए टस्क ने प्रस्ताव रखा कि भारत के बड़े आईटी सेवा क्षेत्र को पोलैंड के स्वचालन, क्लाउड सॉल्यूशन और साइबर सुरक्षा अनुभव के साथ जोड़ा जाना चाहिए.

त्योहारी सीजन से पहले बड़ी राहत

- 31 दिसंबर तक बढ़ी कच्चे चीनी आयात की समयसीमा
- महंगाई को रोकने सरकार ने उठाए एहतियाती कदम

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर. त्योहारी सीजन के दौरान देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और आम उपभोक्ताओं को महंगाई के झटके से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नई अधिसूचना के अनुसार, टैरिफ रेट कोटा के तहत 10 लाख टन कच्चे चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अंतिम समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है. इससे पहले 20 अगस्त को सरकार ने 10 लाख टन कच्चे चीनी के आयात की अनुमति 31 अक्तूबर तक के लिए दी थी. चीनी उत्पादन के अनुमानों में आई गिरावट को देखते हुए सरकार का यह कदम घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती प्रदान करेगा.

देश में आगामी त्यौहारों के दौरान चीनी की खपत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, जिसके लिए पर्याप्त स्टॉक का होना बेहद जरूरी है. सरकार ने 20 अगस्त को ही टैरिफ रेट कोटा के तहत 10 लाख टन कच्चे चीनी के बिना सीमा शुल्क आयात को मंजूरी दे दी थी, जिसकी मियाद 31 अक्तूबर को खत्म हो रही थी.

> घरेलू बाजार में चीनी की किल्लत न हो और कीमतों में कोई अप्रत्याशित उछाल न आए, इसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने आयात खिड़की को दो महीने के लिए आगे बढ़ाते हुए 31 दिसंबर तक कर दिया है. इस विस्तार से भारतीय रिफाइनरियों और आयातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से कच्ची चीनी खरीदने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा. सरकार द्वारा 10 लाख टन आयात की छूट दिए जाने के बावजूद अब तक लगभग 2 .6 लाख टन कच्चे चीनी का ही आयात हो सका है.

अडाणी पावर का मुनाफा दोगुना दूसरी तिमाही में 6,919 करोड़

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। मुंबई 7 अडाणी पावर ने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कंपनी ने मुनाफे और राजस्व दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है.

जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा दोगुना से अधिक बढ़कर 6,919 करोड़ पर पहुंच गया, जो बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,953 करोड़ था. वहीं, कंपनी का ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू 44 प्रतिशत बढ़कर ?19,438 करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 13,457 करोड़ रहा था. कंपनी के शानदार नतीजों का मुख्य कारण देश में बिजली की बढ़ती मांग और सेलिंग रेट्स में आया सुधार है. इस दौरान अडाणी पावर का एबिटा 59.8 प्रतिशत की मजबूती के साथ ?8,231.6 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि इसका एबिटा मार्जिन 4.35 फीसदी सुधरकर 42.35 प्रतिशत हो गया. समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की बिजली बिक्री 11.5 प्रतिशत बढ़कर 26.4 अरब यूनिट रही. बेहतर डेट मैनेजमेंट के बल पर कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट 9.7 प्रतिशत घटकर 760.23 करोड़ रह गई.

ICICI लाइफ के मुनाफे में बढ़ोतरी

पहली छमाही में 760 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

मुंबई, 23 अक्टूबर. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी के व्यक्तिगत सुरक्षा बीमा कारोबार में सालाना आधार पर 47.2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेंशन और नियमित आय देने वाली वार्षिकी योजनाओं के कारोबार में 50% की वृद्धि दर्ज की गई.

इसके परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत बीमा का कुल बीमित मूल्य सालाना आधार पर 34.9% बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह ग्राहकों को मिलने वाले बीमा कवर में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है. कंपनी का नया कारोबार प्रीमियम पहली छमाही में सालाना आधार पर 25% बढ़कर 11,821 करोड़ रुपये हो गया. नए कारोबार का मूल्य (वीएनबी) 22.3% बढ़कर 1,283 करोड़ रुपये रहा, जबकि वीएनबी मार्जिन 26% दर्ज किया गया। इस दौरान, कंपनी का कर पश्चात लाभ (पीएटी) 26.5% की बढ़ोतरी के साथ 760 करोड़ रुपये पर पहुँच गया. आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा, 'ग्राहकों को प्राथमिकता देना हमेशा से आईसीआईसीआई लाइफ के कामकाज का मूल सिद्धांत रहा है और आने वाले वर्षों में भी हमारी सभी गतिविधियों का मार्गदर्शन यही सोच करेगी.

6 आईटी कंपनियों में एक साल में 24,422 कर्मचारी घटे

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर. भारत की टॉप छह आईटी और इंजीनियरिंग कंपनियों में पिछले एक साल के भीतर कुल 24,422 कर्मचारी कम हुए हैं.

इनमें पुराने कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की रफ्तार नई नियुक्तियों से ज्यादा तेज है, जिससे कुल कर्मचारियों की संख्यामें भारी कमी आई है. यह गिरावट भारत की टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, और एलटीआई माइंडट्री कंपनियों में देखी गई है. पिछले एक साल में इन कंपनियों से कुल 92 हजार कर्मचारियों ने एग्जिट किया. कंपनियों ने खाली पदों को पूरी तरह नहीं भरा और केवल 68 हजार नए कर्मचारी ही नियुक्त किए. इसके चलते अक्तूबर 2025 के 8,22,144 कर्मचारियों के मुकाबले अक्तूबर 2026 में इन कंपनियों का कुल वर्कफोर्स लगभग 3% घटकर 7,97,722 रह गया है. इसके पीछे एआई मुख्य वजह है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, मैनुअल टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जैसी पारंपरिक आईटी भूमिकाओं को एआई खुद संभाल रहा है.

व्हाट्सएप्प इस्तेमाल करने वाले सावधान

- डीओटी ला रहा सीम बाइंडिंग नियम
- बिना सिम कार्ड के नहीं चलेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर. अगर आप रजिस्टर्ड नंबर से अलग-अलग फोन में व्हाट्सएप्प या फिर टेलीग्राम चला रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है. जल्द आप बिना सिम कार्ड डाले फोन में वॉट्सऐप समेत अन्य सर्विसेस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार इस सुविधा पर लगाम लगाने वाली है.

भारत सरकार का सिम बाइंडिंग नियम 1 जनवरी से लागू होने वाला है. नए नियम के तहत, वॉट्सऐप और टेलीग्राम चलाने के लिए यूजर्स को अपने फोन में रजिस्टर्ड सिम कार्ड अनिवार्य रूप से डालना होगा, ताकि वे इन मैसेजिंग सर्विसेस का इस्तेमाल जारी रख सकें. सरकार फेक सिम कार्ड और सिम क्लोनिंग से होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए यह नियम ला रही है. ये नियम मोबाइल नंबर और उससे जुड़े अकाउंट के बीच का कनेक्शन और मजबूत करने के लिए हैं, ताकि जालसाजों के लिए मैसेजिंग सर्विसेस का गलत इस्तेमाल या फ्रॉड करना मुश्किल हो जाए. यह नियम लागू होने के बाद, ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है, जो फोन में रजिस्टर्ड सिम नहीं डालते है, बल्कि वाई-फाई के जरिए फोन में वॉट्सऐस, टेलीग्राम चला रहे हैं. नया नियम आईफोन और एंड्रॉयड दोनों तरह के फोन्स पर लागू होगा.

नेटवर्क न होने पर भी काम नहीं रुकेगा : शिवराज

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली , 23 अक्टूबर. ग्रामीण धरातल पर पारदर्शिता और जवाबदेही की नई मिसाल कायम करते हुए केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को एनएमएमएस ऐप के उन्नत फेस ऑथेंटिकेशन संस्करण को औपचारिक रूप से जारी किया.

वीबी-जी राम जी योजना के तहत तैयार इस ऐप को आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है. इसमें गूगल प्ले इंटीग्रिटी, डिवाइस-लेवल सिक्योरिटी और 'लाइवनेस डिटेक्शन' जैसी आधुनिक विशेषताएं शामिल की गई हैं, जिससे फर्जी हाजिरी और बजट की हेराफेरी को जड़ से खत्म किया जा सके. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई 2026 से लागू इस योजना के अंतर्गत देश की 2.41 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में 31.23 लाख कार्यस्थलों पर काम हुआ है. इसके तहत 3.65 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला है और अब तक 46 करोड़ मानवदिवस का सृजन किया जा चुका है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए योजना में 95,692 करोड़ का केंद्रीय बजट प्रावधान किया गया है, जो राज्य के अंश को मिलाकर ?1.51 लाख करोड़ से अधिक हो जाता है. शिवराज ने आश्वस्त किया कि तकनीकी सख्ती के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है. नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में ऑफलाइन उपस्थिति और बुजुर्ग या दिव्यांग श्रमिकों के लिए 'एक्सेप्शन मैकेनिज्म' की व्यवस्था की गई है. एआई आधारित डी-डुप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मापन पुस्तिका के जरिए मजदूरी का सीधा भुगतान खातों में किया जा रहा है. किसानों के हित में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2027 तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले तय समय से एक साल पहले ही 10.99 करोड़ फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं.

CHANGE OF NAME

It is for general information that I, Amit Kumar Pandey S/o Suresh Chandra Pandey R/o 39, Sai Colony, Guda Gudi Ka Naka, Kampoo, Lashkar, Gwalior, Gird, Gwalior, Madhya Pradesh- 474001, declare that name of mine, my father and my mother has been wrongly written as Amit Kumar Panday, Suresh Chandra Panday and Padma Panday in my 10th class Certificate Cum Marksheet . The actual name of mine, my father and my mother is Amit Kumar Pandey, Suresh Chandra Pandey and Padma Pandey respectively, which may be amended accordingly.

उत्तर मध्य रेलवे

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य अभियंता (टीएमसी) लाइन झॉसी निम्नलिखित कार्य के ऑन लाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा सूचना सं0: झॉसी-टीएमसी-10.2026	
कार्य का नाम : एमएलआर एण्ड टेक्नीकल अप-ग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग HOT CSM (CSM 960, 966 & 972) द्वारा HOTS-CSM मशीन (लेटेस्ट अवेलएबिल) वर्किंग ऑवर नार्थ सेन्ट्रल रेलवे एज पर स्कोप ऑफ वर्क	
अनुमानित लागत (Rs.) : 48,46,57,683.00	**धरोहर राशि** (Rs.) : 96,93,200.00
निविदा बन्द होने की तिथि : 16.11.2026	**कार्य समापन अवधि :** 12 माह (एक वर्ष)

• निविदा उनके सामने दर्शायी गई तिथि को 15:00 बजे तक ऑन लाइन जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रेल की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें। निविदा सूचना का विवरण उपरोक्त कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। 2409/26 (AS)

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @CPRONCR

उत्तर मध्य रेलवे

ई-प्राप्ण निविदा सूचना संख्या 10/2026-27 दिनांक 23/10/2026

ई-प्राप्ण निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल सामग्री प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, झांसी द्वारा निम्नलिखित मद के लिए ई-प्राप्ण निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा संख्या 92267527	विवरण : एसएमपीएस आधारित एकीकृत विद्युत आपूर्ति (आईपीएस) प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना एवं कमीशनिंग आरडीएसओ/एसपीएन/165/2023, संस्करण 4.0, संशोधन 1 या नवीनतम के अनुसार...... ई-प्राप्ण निविदा के अनुसार
मात्रा : 3 नग + 3 नग	निविदा खुलने की दिनांक : 17/11/2026

नोटः उपरोक्त ई-प्राप्ण निविदा का पूरा विवरण IREPS वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा में किसी भी बदलाव/शुद्धि-पत्र के लिए कृपया इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखें। समाचार-पत्र में कोई अलग से शुद्धि-पत्र/परिवर्तन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। कोई मैनुअल प्रस्ताव/बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। 2419/26 (D)

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

IDFC FIRST Bank

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार प्रभार लगेगा।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	157193345	संपत्ति के बदले ऋण	06-Oct-2026	53,22,579.42/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नामः 1. प्रीति साहू 2. मनोहर साहू

संपत्ति का पताः संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 60 x 68 = 4080 वर्ग फुट (यानी 379.18 वर्ग मीटर) है (पूर्व से पश्चिमः 68 फुट और उत्तर से दक्षिणः 60 फुट)। यह संपत्ति आराजी सर्वे नंबर 1124 का हिस्सा है, जो पीएच नंबर 19, वार्ड नंबर 02, छल्लापुरा, मौजा दतियागिर्द, R.N.M-दतिया, तहसीलः दतिया, जिलाः दतिया, मध्य प्रदेश-475661 में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्वः साहू की संपत्ति, पश्चिमः साहू की संपत्ति, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः आम रास्ता।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री/पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

दिनांकः 24.10.2026 | स्थानः मध्यप्रदेश

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

ICAR-National Research Centre for Grapes
Manjiri Farm, P B, No 3, Solapur Rd, Pune, Maharashtra 412308

Invitation for Bids

Date: 22nd October 2026
Tender ID: 2026_DAREA_931233_1
Loan No. and Title: Loan 4411-IND/Building India's Clean Plant Program
Contract No. and Title: CPC1-CW01/ Design and Build containment facility for grapes - CPC 1, Pune
Deadline for Submission of Bids: 03 December 2026

1. The Government of India has received financing from the Asian Development Bank (ADB) toward the cost of Building India's Clean Plant Program. Part of this financing will be used for payments under the Contract named above. Bidding is open to Bidders from eligible source countries of ADB.
2. The Principal Scientist (Plant Pathology), ICAR-National Research Centre for Grapes, Pune ("the Employer") invites sealed bids from eligible Bidders for the construction and completion of Design and Build containment facility for grapes - CPC 1, Pune including comprehensive Operation and Maintenance for a period of five (5) years from date of handover ("the Works")."
3. Open competitive bidding will be conducted in accordance with ADB's Single-Stage: Two-Envelope bidding procedure and is open to all Bidders from eligible countries as described in the Bidding Document.
4. Only eligible Bidders with the following key qualifications defined in the Bidding Document may participate in this bidding:
   - Minimum average annual turnover of **INR 380 million (USD 4M)** within the last three (3) years; For the complete eligibility and qualification requirements, Bidders should refer to the Bidding Document.
   - Participation as a contractor, Joint Venture partner, or Subcontractor, in at least one (1) contract satisfactorily and substantially completed within the last seven (7) years from the date of bid submission, where the value of the Bidder's participation exceeds **INR 190 million (USD 2 million)**, OR at **least two (2)** contracts each **≥ INR 114 million (USD 1.2 million)**, satisfactorily completed within the last seven (7) years.
5. To obtain further information and inspect the bidding documents, Bidders should contact:
   The Principal Scientist (Plant Pathology)
   ICAR-National Research Centre For Grapes,
   P.B. No. 3, P.O. Manjiri Farm, Solapur Road,
   Pune-412307, Maharashtra, India
   Telephone 020 2695 6000
   Web: https://nrcgrapes.icar.gov.in/
   Email: sujoyta@gmail.com
6. To purchase the Bidding Document in English, eligible Bidders should
   - register and download the bidding documents from Employer's procurement portal https://eprocure.gov.in/eprocure/app
   - The Employer shall not be held liable for any information not received by the Bidder, and it is the Bidder's responsibility to regularly check the website for the latest information related to this invitation for bids.
   - The Bidding Documents are available for free download from the Employer's e-procurement portal. No fee is payable.
7. Deliver your bid
   - Bidders shall submit their Bids electronically only through the public procurement website https://eprocure.gov.in/eprocure/app on or before the deadline: Date: 03 December 2026 Time: 11:00 hours
   - together with a Bid Security as described in the Bidding Document
   Technical Bids will be opened publicly online on: Date: 03 December 2026, Time: 11:15 hours (IST), via the e-procurement portal https://eprocure.gov.in/eprocure/app and at: ICAR-National Research Centre for Grapes, P.B. No. 3, P.O. Manjiri Farm, Solapur Road, Pune - 412307. Price Bids will be opened at a date and time to be notified to qualifying bidders following Technical Bid evaluation.
8. This Invitation for Bid is also published on the following websites
   https://eprocure.gov.in/eprocure/app
   https://nhb.gov.in/
   https://www.nrcgrapes.in/
   https://www.adb.org/projects/57041-001/main

Sd/-
Administrative Officer